ज्ञान तत्व 376

मंथन क्रमांक–91 ''स्वतंत्रता और समानता की एक समीक्षा''

1 प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिकाए होती है। 1 व्यक्ति के रूप मे 2 समाज के अंग के रूप मे। दोनो भूमिकाए बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी कुछ मामलो मे एक दूसरे की पूरक होती है।
2 जब तक व्यक्ति अकेला है तब तक वह व्यक्ति है एक से अधिक होते ही वह समाज का अंग बन जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता असीम होती है किन्तु एक से अधिक होते ही सबकी स्वतंत्रता समान हो जाती है।
3 असीम स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार होता है। यह सीमा वहां तक होती है जहां से किसी अन्य की स्वतंत्रता का उल्लंघन न होता हो।
4 प्राकृतिक रूप से कोई भी दो व्यक्ति किसी भी मामले मे समान नही होते । असमानता प्राकृतिक है और समानता के प्रयत्न करना षणयंत्र।
5 समान स्वतंत्रता प्राकृतिक सिद्धान्त है । समान करने का प्रयास ऐसी समानता को असमान बनाता है।
6 कमजोरो की मदद करना मजबूतो का कर्तब्य होता है, कमजोरो का अधिकार नही । राजनैतिक षणयंत्र इसे कमजोरो का अधिकार बताता है और निकम्मे लोग इस षणयंत्र को अपना हथियार बनाते हे।
7 व्यक्ति दो प्रकार के होते है भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान । हर बुद्धि प्रधान बिल्लियो के बीच बंदर की भूमिका मे भावना प्रधान लोगो को ठगने के लिये समानता दूर करने के प्रयास को हथियार बनाते है ।
8 हर बुद्धि प्रधान अपने से उपर वाले से स्वतंत्रता चाहता है और अपने से नीचे वालो को स्वतंत्रता नही देना चाहता।
9 गरीब अमीर उंच नीच छोटा बडा, कमजोर और मजबूत भ्रामक शब्द है । हर व्यक्ति अपने से मजबूत की अपेक्षा कमजोर और कमजोर की अपेक्षा मजबूत समझता है। यह सापेक्ष शब्द है निर्पेक्ष नही।

वैसे तो पूरी दुनियां मे समानता के नाम पर बहुत बडा षणयंत्र चल रहा है किन्तु भारत मे इसका दूष्प्रभाव सबसे ज्यादा है। समानता लाने के नाम पर जो भी प्रयत्न किये जा रहे है वे सब हर मामले मे असमानता को बढा रहे है। इस मामले मे सबसे अधिक सक्रियता तंत्र से जुडे लोगो की है। ऐसे लोग आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करने के नाम पर निरंतर राजनैतिक असमानता बढाते जाते है। यहां तक कि असमानता दूर करने के नाम पर ही तंत्र ने लोक को इतना गुलाम बना लिया है कि वोट देने के अतिरिक्त लोक के पास कोई ऐसी स्वतंत्रता नही बची है, जो तंत्र की दया पर निर्भर न हो। गली गली मे जाति प्रथा छुआछूत महिला उत्पीडन अमीरी और गरीबी रेखा के नाम पर दुकाने खुली हुई है और लगभग सबके तार राजनैतिक सत्ता के प्रयत्न से जुडे दिखते है। राजनीति के नाम पर अलग अलग गिरोह बने हुए है जो समाज के समक्ष तो आपस मे टकराने का नाटक करते है किन्तु खतरा दिखते ही सब एक हो जाते है। समझ मे नही आता कि 12जब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता समान है तथा संवैधानिक अधिकार भी एक बराबर है तब ये राजनैतिक नेता और समाज सुधारक किस बात को बराबर करना चाहते है। जब व्यक्तिगत क्षमता प्राकृतिक रूप से असमान होती ही है और उसे किसी भी तरह समान नही किया जा सकता तो फिर समानता के प्रयत्नो का औचित्य क्या है? प्रश्न यह भी उठता है कि समान अधिकारो वाला व्यक्ति कैसे किसी दूसरे की असमानता दूर कर सकता है। किसी भी व्यक्ति या राज्य का यह अधिकार है कि वह किसी भी अन्य की किसी भी रूप मे मदद कर सकता है किन्तु किसी को यह अधिकार नही है कि वह किसी अन्य के अधिकार काटकर किसी अन्य को दे सके क्योकि अधिकार सबके समान होते है।

समान स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है । इसमे किसी प्रकार का बदलाव न उचित है न संभव । बिना व्यक्ति की सहमति के इसकी स्वतंत्रता मे कोई कटौती नही की जा सकती। यह भी आवश्यक है कि उसकी सहमति के बाद भी उसकी स्वतंत्रता मे कोई मौलिक समझौता नही किया जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई समझौता उसकी सहमति के बाद भी तभी तक लागू रह सकता है जबतक उसकी सहमति है। अन्यथा वह समझौता समाज के लिये विचार का आधार बनेगा। ऐसी परिस्थिति मे राज्य समाज की सहमति से बनी हुई एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असीम स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस तरह समानता की यह परिभाषा बनती है कि किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित सीमा रेखा से नीचे वालो को समान सुविधा तथा उपर वालो को समान स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिये। स्वाभाविक है कि राज्य इस निमित्त सबसे अधिक उपयुक्त व्यवस्था है । समाज इस व्यवस्था मे सहायता कर सकता है। मेरे विचार मे किसी प्रकार की असमानता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि समानता के

लिये किये जाने वाले सारे प्रयत्न बंद कर दिये जाये क्योकि ये कानूनी प्रयत्न ही असमानता के प्रमुख कारण है। परिणाम स्वरूप अपने आप सबकी स्वतंत्रता समान हो जायेगी और किसी को कोई प्रयत्न नही करना होगा।

मंथन क्रमांक–92 ''सन् 75 का आपातकाल और वर्तमान मोदी सरकार की एक समीक्षा''

कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है

1 शासन का संविधान तानाशाही होती है और संविधान का शासन लोकतंत्र। तानाशाही मे व्यक्ति के मौलिक अधिकार नही होते जबकि लोकतंत्र मे होते है।

2 लोकतंत्र दो तरह का होता है। 1 आदर्श और विकृत । आदर्श लोकतंत्र मे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रकृत्ति प्रदत्त होते है और विकृत लोकतंत्र मे मौलिक अधिकार संविधान देता है और ले सकता है।

3 दुनियां मे लोकतंत्र कई प्रकार का है । संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपतीय प्रणाली, सहभागी लोकतंत्र, तानाशाही लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और साम्यवादी देशो का तानाशाही लोकतंत्र माना जाता है।

4 सुशासन और स्वशासन मे बहुत फर्क होता है। स्वशासन आदर्श लोकतंत्र है सुशासन विकृत। सुशासन लोकतंत्र मे भी संभव है और तानाशाही मे भी।

5 आदर्श लोकतंत्र मे लोक नियंत्रित तंत्र होता है। लोक मालिक और तंत्र प्रबंधक। तानाशाही मे तंत्र मालिक और लोक गुलाम रहता है।

6 भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से तंत्र की तानाशाही के रूप मे है, आदर्श लोकतंत्र नही । यहां तंत्र मालिक है और लोक गुलाम।

7 जब न्याय और कानून मे टकराव होता है तब आदर्श लोकतंत्र मे न्याय महत्वपूर्ण होता है और विकृत लोकतंत्र मे कानून।

8 विकृत लोकतंत्र मे संगठन शक्तिशाली होते है, संस्थाए कमजोर । आदर्श लोकतंत्र मे संस्थाए मजबूत होती है संगठन कमजोर।

सन 75 मे इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत कारणो से आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल मे सरकार ने घोषणा की थी कि मौलिक अधिकार निलंबित कर दिये गये है। घोषणा के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना कारण बताये गोली मार सकती थी। संसद और न्यायपालिका पर असंवैधानिक तरीके से नियंत्रण कर दिया गया था। सरकार की समीक्षा करने पर भी प्रतिबंध लग गया था। आलोचना या विरोध का तो कोई प्रश्न ही नही था। उस समय का आपातकाल पूरी तरह व्यक्तिगत तानाशाही थी क्योकि भारत का संविधान किसी व्यक्ति का गुलाम बन गया था। दो वर्ष बाद सन 77 मे फिर से विकृत लोकतंत्र की स्थापना हुई जो अब तक जारी है।

चार वर्ष पूर्व भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मे आमूल चूल बदलाव दिखा। नरेन्द्र मोदी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद 70 वर्षो से लगातार जारी शासन व्यवस्था के तरीके मे आमूलचूल परिवर्तन किये जिसके अच्छे और बुरे परिणाम भी दिखे और आगे भी दिखेगे। मोदी सरकार ने चुनावो के पूर्व जनता से जो वादे किये उनमे से कोई भी वादा पूरा नही हुआ। क्योकि असंभव वादे कर दिये गये थे चाहे 15 लाख की बात हो अथवा रोजगार देने की या भ्रष्टाचार समाप्त करने की । अब भी मोदी सरकार ऐसे ही असंभव वादे करती जा रही है जो पूरे नही हो सकते। वर्तमान सरकार सिर्फ उन्ही कार्यो को आगे बढा रही है जो पिछली सरकारो के समय योजना मे थे या शुरू हुए थे। सिर्फ कार्य प्रणाली बदली है। फिछली सरकार किसी कार्य को पांच वर्ष मे पूरा करने की गति से चलती थी तो वर्तमान सरकार उसे एक वर्ष मे पूरा करने की घोषणा कर देती है। स्वाभाविक रूप से कार्य मे एक की तुलना मे डेढ दो वर्ष लग जाते है । अब इस विलंब को वर्तमान सरकार की सफलता माने या असफलता । लगभग सब प्रकार के कार्यो की गति बहुत तेज हुई है और घोषणा उससे भी अधिक तेज गति की कर दी जाती है। पिछली सरकारे नौकरी को ही रोजगार मानकर चलती थी वर्तमान सरकार ने पकौडा पौलिटिक्स के माध्यम से रोजगार को श्रम के साथ जोडने की शुरूआत की किन्तु हिम्मत टूट गई और फिर उसी परिभाषा पर सरकार आ गई है। वर्तमान सरकार आने के बाद राजनैतिक भ्रष्टाचार मे बहुत कमी आई है। सरकारी कर्मचारियों के भी भ्रष्टाचार मे आंशिक कमी आई है किन्तु जैसा वादा किया गया था उस तरह तेजी से भ्रष्टाचार घट नही रहा है। राजनीति मे परिवार वाद का समापन दिखने लगा है। अब नेहरू गांधी परिवार या लालू मुलायम राम विलास करूणा निधि जैसे परिवारो के राजनैतिक सत्ता विस्तार के दिन गये जमाने की बात बन गये है। अब ये लोग धीरे धीरे या तो अस्तित्वहीन हो जायेगे अथवा अपने मे बदलाव करेंगे। अखिलेश यादव परिवार की अपेक्षा अपनी स्वतंत्र योग्यता पर आगे बढ रहे है किन्तु उन्होने भी मुख्यमंत्री निवास खाली करने के मामले मे अपने उपर एक कलंक

जोड लिया है। स्वाभाविक है कि अब भारत मे परिवार वाद के नाम पर राजनीति नही चल पायेगी। वैसे तो लगभग बीस वर्षो से ये लक्षण दिखने लगे थे कि राजनीति मे अच्छे लोग ही आगे बढ पायेंगे। अटल जी मनमोहन सिंह नीतिश कुमार अखिलेख यादव नरेन्द्र मोदी सरीखे अच्छे लोग समाज मे सम्मान पाते रहे और गंदे लोग धीरे धीरे कमजोर होते गये । अब नरेन्द्र मोदी के बाद यह बात और मजबूती से आगे बढी है कि राजनीति मे अच्छे लोग ही आगे बढ पायेगे चाहे वे सत्ता पक्ष मे हो अथवा विपक्ष मे।

नरेन्द्र मोदी ने अपने चार वर्षो के कार्यकाल मे सीधा सीधा ध्रुवीकरण कर दिया है। 70 वर्षो तक जो लोग पक्ष विपक्ष मे विभाजित होकर सम्पूर्ण समाज का मार्ग दर्शन और नेतृत्व कर रहे थे उन सब लोगो को नरेन्द्र मोदी ने किनारे लगा दिया है। सम्पूर्ण विपक्ष तो पूरी तरह नाराज है ही किन्तु सत्ता पक्ष के भी करीब करीब सभी लोग नरेन्द्र मोदी से नाराज है । भले ही वे डर से समर्थन क्यो न करते हो । लगभग सभी संगठन मोदी से नाराज है चाहे वे हिन्दू संगठन हो या मुस्लिम इसाई संगठन। व्यापारी संगठन भी नरेन्द्र मोदी से नाराज हैं चाहे वे बडे उद्योग पति हो या छोटे व्यापारी । मीडिया मे भी नरेन्द्र मोदी के प्रति भारी असंतोष है भले ही कुछ लोग उनसे लाभ लेकर उपर उपर उनका गुणगान कर रहे हो । किसान संगठन के लोग हो या श्रमिक संगठन सब नरेन्द्र मोदी की नीतियो से असंतुष्ट है। सवर्णो के संगठन और अवर्णो के संगठन भी नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध इकठठे हो रहे है। गाय गंगा मंदिर के पक्षधर भी उनसे नाराज है तो इनके विरोधी भी। राजनैतिक सामाजिक धार्मिक व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति मोदी से खुश नही है जो अपनी ताकत पर सौ पचास वोट दिलवाने की हिम्मत रखता हो। यहां तक कि एन डी ए मे शामिल घटक दल भी पूरी तरह मोदी के खिलाफ है। इसका मुख्य कारण यह है कि 15मोदी किसी की बात नही सुनते जो उनको ठीक लगता है वह बिना किसी की सलाह लिये स्वयं करते है। वे हर मामले मे स्वतंत्र रूप से तकनीकी लोगो की टीम बनाकर उससे जांच कराते है और किसी के दबाव मे नही आ रहे है।यहां तक कि संघ परिवार जिसका ताकत पर मोदी प्रधान मंत्री बने उसकी भी इन्होने कभी कोई विशेष परवाह नही की । मै जानता हूॅ कि सिर्फ एक बार बडी मुस्किल से कुछ आर्थिक मुददे पर नरेन्द्र मोदी भागवत जी के दबाव मे आये थे और उस दबाव के कारण जो अर्थनीति मे थोडा बदलाव किया गया उसके दुष्परिणाम भी हुए। अन्यथा किसी और मामले मे मोदी किसी अन्य के दबाव मे नही झुके। यही कारण है कि देश के लगभग सभी सरकार के सहयोगी और मोदी विरोधी एक स्वर से उन्हे तानाशाह कहने लगे है। मै समझता हूॅ कि नरेन्द्र मोदी ने यह जुआ खेला है। इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते है और बुरे परिणाम भी। नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से सीधे मतदाताओ को संबोधित कर रहे है न कि बिचौलियो के माध्यम से। बिचौलियो को किनारे करके सीधे मतदाताओ से संपर्क करने का उनका प्रयास कितना सफल होगा । यह तो 2019 मे ही पता चलेगा । । वास्तव मे लीक छोडकर मोदी ने जो मार्ग अपनाया है वह अप्रत्यक्ष रूप से राष्टपतीय प्रणाली की ओर जाता है जिसका अर्थ है जनता राष्टपति का चुनाव करती है और राष्टपति शक्तिशाली व्यक्ति होता है। 70 वर्षो से चली आ रही राजनैतिक व्यवस्था मे वोटो के व्यापारी जिस प्रकार बिचौलिये की भूमिका निभाते थे वे समाप्त होगे या एक जुट होकर नरेन्द्र मोदी को समाप्त कर देंगे। यह अभी स्पष्ट नही कहा जा सकता।

मै कोई भविष्य वक्ता नही हूॅ। मै तो स्पष्ट देख रहा हूॅ कि एक तरफ साम्प्रदायिकता जातियता संगठनवाद और सत्ता की जोड तोड मजबूती के साथ खडी है तो दूसरी तरफ नरेन्द्र मोदी ने अंगद का पैर इस तरह जमा दिया है उसे हिलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। मै तो व्यक्तिगत रूप मे साम्प्रदायिकता जातिवाद परिवारवाद संगठनवाद का विरोधी हूॅ किन्तु मै इस कार्य मे मोदी जी की कोई मदद नही कर पा रहा क्योकि मुझे अपने वोट देना नही है । वोट दिलाना भी नही है। मै तो जब तक भारत मे मोदी या कोई अन्य विकृत लोकतंत्र की उठा पटक को छोडकर आदर्श लोकतंत्र अर्थात लोक स्वराज्य या सहभागी लोकतंत्र की दिशा मे नही बढेगा तब तक मै कुछ करने की स्थिति मे नही हूॅ। इसलिये मै तो सिर्फ मोदी के सशक्त होने के लिये ईश्वर से प्रार्थना मात्र कर सकता हूॅ। मैने तो पिछले चुनाव के पूर्व मे मनमोहन सिंह के लिये भी ऐसी प्रार्थना की थी। किन्तु सोनियां गांधी ने पुत्र मोह मे पडकर मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था और मनमोहन सिंह सरीखे एक लोक तांत्रिक संज्जन महापुरूष को राजनीति से असफल सिंद्ध किया गया था। उस समय ईश्वर ने मेरी नही सुनी अब क्या होगा मुझे पता नही।

नरेन्द्र मोदी से आम जनता को जिस प्रकार की उम्मीदे थी वे पूरी नही हुई , किन्तु पिछले 70 वर्षो मे जितने भी प्रधान मंत्री हुए है उन सबकी तुलना मे नरेन्द्र मोदी ने बहुत कम समय मे बहुत अच्छा काम किया है। अब पुरानी व्यवस्था का तो समर्थन नही किया जा सकता। और यदि नरेन्द्र मोदी से भी कोई अच्छी व्यवस्था दिखाई देती है तब आम लोग वैसा प्रयोग कर सकते है। नीतिश कुमार अखिलेश यादव से अभी भी बहुत उम्मीदे बनी हुई है। नरेन्द्र मोदी उम्मीद से कई गुना अच्छा कार्य कर रहे है और अपनी नई प्रणाली के आधार पर प्रमुख लोगो को नाराज भी कर रहे है। इतिहास रचते रचते गोर्वा चोव गायव हो गये। मोदी का क्या होगा यह भविष्य बतायेगा।

मंथन क्रमांक–93 ''डालर और रूपये की तुलना कितना वास्तविक कितना प्रचार''

कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है।
1 समाज को धोखा देने के लिये चालाक लोग परिभाषाओ को ही विकृत कर देते है उससे पूरा अर्थ भी बदल जाता है। ऐसी विकृत परिभाषा को प्रचार के माध्यम से सत्य के समान स्थापित कर दिया जाता है।
2 दुनियां मे परिभाषाओ को विकृत करने का सबसे अधिक प्रयास साम्यवादियो ने किया और सबसे कम मुसलमानो ने।
3 दुनियां मे योजना पूर्वक पचासो परिभाषाए पूरी तरह बदल दी गई है। इनमे मंहगाई बेरोजगारी गरीबी महिला उत्पीडन आदि अनेक परिभाषाए शामिल है।
4 गुलामी के बाद भारत मे अपना चिंतन बंद हो गया और भारत सिर्फ नकल करने लगा। साम्यवाद और पश्चिम की विकृत परिभाषाओ को भारत मे सत्य के समान मान लिया गया जो अब तक जारी है।
5 मंहगाई सेन्सेक्स बेरोजगारी जी डी पी रूपये का मूल्य ह्रास आदि से सारा भारत चिंतित है जबकि उनमे से किसी का भारत की सामान्य जनता पर अब तक कोई अच्छा बुरा प्रभाव नही पडा।
6 मंहगाई जी डी पी बेरोजगारी रूपये का मूल्य ह्रास सेन्सेक्स आदि का सामान्य अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडने का प्रचार काल्पनिक है यथार्थ नही।

अपने 65 वर्षो के लगातार चिंतन के बाद भी मै कभी नही समझा कि मंहगाई बेरोजगारी जी डी पी का भारत के सामान्य जन जीवन पर क्या और कितना अच्छा बुरा प्रभाव पडा। स्वतंत्रता के बाद मंहगाई कितनी बढी और उसका क्या प्रभाव पडा यह बताने वाला कोई नही। कौवा कान ले गया और अपना कान न देखकर कौवे के पीछे पूरा भारत भाग रहा है। भारत मे आवश्यक वस्तुओ मे मंहगाई स्वतंत्रता के बाद करीब 60 गुनी बढी है और औसत जीवन स्तर इसके बाद भी सुधर कर करीब चार गुना बढ गया। सेन्सेक्स घटने बढने का तो प्रभाव कुछ समझ मे ही नही आता। जी डी पी भी हर साल घटते बढते रहता है लेकिन न कभी अच्छा प्रभाव दिखा न कभी बुरा। बेरोजगारी घटने बढने का भी कोई अच्छा बुरा प्रभाव आज तक स्पष्ट नही हुआ क्योकि इन सबकी जान बुझकर परिभाषाए बदलने मे पश्चिम की नकल की गई । जब परिभाषा ही बदल दी गई तब वास्तविक अर्थ का पता ही नही चलेगा। यदि आपको दो और दो पांच लगातार पढाया जाये तो उससे आपके निष्कर्ष गलत होना स्वाभाविक है। दोष निष्कर्ष निकालने वाले का नही है बल्कि गलत परिभाषा का है।

भारत मे डालर की तुलना मे रूपये के गिरते मूल्य की बहुत चिंता हो रही है। देश का हर आदमी चिंता कर रहा है कि रूपये का मूल्य गिरकर 70 रूपये के आस पास हो गया है। मै तो भावनात्मक रूप से इन सारे प्रचार को षणयंत्र मानता हूॅ क्योकि यदि वास्तव मे डालर की तुलना मे रूपया स्वतंत्रता के बाद 70 गुना गिर गया तो उसका प्रभाव भारत की अर्थ व्यवस्था पर अब तक कितना पडा यह बताने वाला कोई नही है। आर्थिक दृष्टि से जो भी लोग अखबारो मे या टी. वी. मे इस मूल्य ह्रास की चर्चा करते है वे पश्चिम की किताबे पढकर उस गलत परिभाषा के आधार पर परिस्थितियो का आकलन करते है जबकि परिभाषा गलत होने से सारे परिणाम भी गलत हो जाते है । मै दशको से सुनता रहा हूॅ कि डालर की तुलना मे रूपया गिर गया और उसके प्रभाव से भारत पर विदेशो का कर्ज बढ गया । लेकिन मै आज तक नही समझा कि कर्ज बढा या नही और यदि बढा तो कितना बढा और उसका भारत की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव क्यो नही दिखा। सन 47 मे एक डालर का मूल्य एक रूपये के बराबर था जो आज करीब 70 रूपये के बराबर हो गया है तो क्या भारत पर विदेशो का कर्ज 70 गुना बढ गया । मैने इस संबंध मे जब अपनी परिभाषाओ के आधार पर सोचना समझना शुरू किया तो मुझे स्पष्ट दिखा कि ये सबकुछ भ्रम पैदा करने का प्रभाव है । न तो भारत पर कोई कर्ज बढा है न कोई उसका प्रभाव पडा है।

एक आकलन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत मे अपने रूपये का आंतरिक मूल्य करीब 95 रूपये के बराबर हो गया है । इसका अर्थ हुआ कि भारत मे जो औसत वस्तुए उस समय एक रूपये मे मिलती थी वे यदि आज 95 रूपये मे मिलती है तो इस प्रकार का कोई बदलाव नही हुआ है। न कोई चीज सस्ती हुई है न मंहगी। स्पष्ट है कि इस आधार पर भारत मे डालर का मूल्य भी 95 रूपये होना चाहिये था जो अभी 70 रूपये के आस पास है। इसका भी एक कारण है भारत मे स्वतंत्रता के बाद औसत मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत वार्षिक की है । प्रत्येक 10 वर्ष मे रूपये की किमत आधी हो जाती है अमेरिका मे डालर का मूल्य 10वर्षो मे 10 प्रतिशत के आसपास ही घटता है । यही कारण है कि जहां 12 रूपये का आंतरिक मूल्य 10 वर्षो मे दो गुना हो जाता है वही डालर की तुलना मे रूपये का मूल्य 12 वर्षो मे दो गुना होता है। अर्थात यदि सन 47 मे

डालर एक रूपया के बराबर था तो बारह वर्षो के बाद दो के बराबर चालिस वर्षो के बाद करीब आठ के बराबर और अब सत्तर वर्षो के बाद करीब 75 रूपये के बराबर होना चाहिये था जो अभी 70 के आसपास है। स्पष्ट है कि रूपया अब भी डालर की तुलना मे कुछ मजबूत है। यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह के कार्य काल मे डालर को साठ होना चाहिये था किन्तु 44 पर रूका था। स्पष्ट है कि आर्थिक मामलो मे मनमोहन सिंह बहुत अधिक सिद्ध हस्त थे।

विदेशी कर्ज रूपये के आधार पर कभी घटता बढता नही है। 13कल्पना करिये कि सन 47 मे शक्कर एक रूपया अर्थात डालर की दो किलो उपलब्ध थी। यदि हम पर 100 डालर का कर्ज था तो उसके बदले हमे दो सौ किलो शक्कर देनी पडेगी। आज भी यदि हम पर 100 डालर का कर्ज है और शक्कर 70 रूपये के बराबर है तो हमे 200 किलो ही शक्कर देनी है। 14रूपया वस्तु का स्थान नही ले सकता । बल्कि वह तो सिर्फ एक विनिमय माध्यम है। रूपये के आंतरिक मूल्य घटने बढने का विदेशी लेने देन पर कोई अच्छा बुरा प्रभाव तब तक नही होता जब तक लेन देन विदेशी मुद्रा मे न होकर भारतीय मुद्रा मे न हो । आम लोगो को आर्थिक मामलो मे धोखा देने के लिये घाटे का बजट जान बूझकर बनाया जाता है जिससे मंहगाई मुद्रा स्फीति और अन्य अनेक आर्थिक भ्रम फैलाने मे सुविधा हो ।

आयात निर्यात भी इसमे बहुत प्रभाव डालता है। यदि आयात अधिक होगा और निर्यात कम तो अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पडना निश्चित है। सरकारे राजनैतिक लाभ के लिये कभी नही चाहती हैं कि आयात निर्यात का संतुलन हो । क्योकि यदि आयात कम होगा तो सुविधाएं घटेगी। झुठे वादे और यथार्थ के बीच अंतर बढ जायेगा। इसका राजनैतिक दुष्प्रभाव स्वाभाविक है। स्पष्ट दिखता है कि डीजल पेट्रोल का आयात सबसे बडी समस्या है। वर्तमान समय मे इसे कम करने का किसी तरह का कोई प्रयास नही हो रहा है क्योकि खाडी देशो से संबंध भी सुधारने है । साथ ही डीजल पेट्रोल के आयात के खेल मे दो नम्बर का भी काम बहुत होता है और आयात कम करने से आवागमन मंहगा होगा जिससे मध्यम उच्च वर्ग का आक्रोश झेलना पडेगा। इसलिये कोई भी सरकार सब कुछ कर सकती है किन्तु डीजल पेट्रोल का आयात घटने नही देगी। आवागमन कभी मंहगा नही होने देगी।

मैने यह लेख मंथन के अंतर्गत लिखा गया है कोई अंतिम निष्कर्ष नही है । मै नही कह सकता कि मेरे लेख मे सभी निष्कर्ष सही होंगे किन्तु मै अपने साथियो से जानना चाहता हूॅ के मेरे चिंतन मे कहां गलत है और क्या गलत है । यदि कोई बात गलत होगी तो मै सुधारने के लिये सहमत हूॅ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि विदेशो की नकल करके असत्य को सत्य के समान स्थापित करने की भारतीय आदत को चुनौती देनी चाहिये । इसी उददेश्य से मंथन के अंतर्गत यह लेख लिखा गया है।

सामयिकी

स्वतंत्रता के बाद नरेन्द्र मोदी भारत के अकेले ऐसे प्रधान मंत्री हुए है जिन्होने खतरे उठाकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये। नोटबंदी एक ऐसा ही निर्णय था किन्तु दो दिन पूर्व मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियो के संबंध मे निर्णय लेकर नोटबंदी से भी अधिक बडा कदम उठा लिया। नोटबंदी का प्रभाव मोदी की तुलना मे देश पर अधिक पडना था किन्तु कर्मचारी नीति बदलाव मोदी की व्यक्तिगत लाभ हानि के साथ जुडा है। स्पष्ट है कि यह चुनावी वर्ष है और कोई भी सरकार चुनाव के समय सरकारी कर्मचारियो के विरूद्ध कोई कदम नही उठाती क्योकि आम चुनावों मे कर्मचारी पांच से सात प्रतिशत तक वोट इधर उधर करने की ताकत रखते है।

आम तौर पर राजनेता और सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार मे एक दूसरे के पूरक होते है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मे एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भ्रष्टाचार ही ही नही सकता। नरेन्द्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियो के विरूद्ध यह कदम उठाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि नरेन्द्र मोदी पूरी तरह भ्रष्टाचार के विरूद्ध कमर कस कर सक्रिय हैं।

विकास और प्रशासन सरकारी कर्मचारियो के माध्यम से ही होता है। अंग्रेजो के समय मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इसलिये सभी कर्मचारियो के उपर राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के लोगो को बिठाया गया। इस बात को कोई महत्व नही दिया गया कि उनकी विभागीय योग्यता और अनुभव कितना है । नरेन्द्र मोदी ने विकास को अधिक महत्वपूर्ण माना। यही सोचकर उन्होने अपनी नीति इस प्रकार बदली जिसमे प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओ का महत्व खतम हो गया।

मैं लम्बे समय से निजीकरण का पक्षधर रहा हूँ। नरेन्द्र मोदी का यह कदम आंशिक रूप से निजीकरण की ओर बढा हुआ माना जायेगा । यद्यपि मै पूरी तरह निजीकरण का पक्षधर रहा हूँ किन्तु यदि आंशिक भी होता है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिये। लोकतंत्र मे नेता ओर कर्मचारी एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते है। इनमे से कोई भी एक दूसरे के सहयोग के बिना गलत नही कर सकता। यदि राजनेताओ की नीयत खराब है तो मजबूत प्रशासनिक सेवा समाज हित मे है। क्योकि ऐसे लोग राजनेताओ की मनमानी को रोक सकते है। यदि राजनेताओ की नीयत ठीक है तो प्रशासनिक सेवा का मजबूत होना जनहित के विरूद्ध जायेगा। क्योकि प्रशासनीक सेवा के लोग अपनी शक्तियो का दुरूपयोग करके किसी कार्य को आगे बढने ही नही देगे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नरेन्द्र मोदी का उपरोक्त निर्णय जनहित मे है भले ही उनके राजनैतिक हितो पर बुरा प्रभाव ही क्यो न डाले। एक बात और है कि भारत अघोषित रूप से राष्ट्रपतीय प्रणाली की ओर बढ रहा है। चुनाव दल की अपेक्षा व्यक्ति ओर परिवार के आधार पर लडे जा रहे हैं। पहली बार परिवारो की तुलना मे व्यक्ति केन्द्र बिन्दु बना है। राष्टपतीय प्रणाली मे प्रशासनीक सेवा सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार होती है। इस आधार पर भी नरेन्द्र मोदी का कदम ठीक माना जायेगा।

मैं इसे आदर्श स्थिति नही मानता । आदर्श स्थिति तो यह होती है कि कार्यपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होती है और विधायिका कानून बनाने तक सीमित रहती है। विधायिका के ही कुछ लोग कार्यपालिका के नाम पर एक अलग समूह बना ले और उस समूह को ही सरकार कहने लग जाये यह घाल मेल आदर्श लोकतंत्र नही है किन्तु वर्तमान समय मे जो कार्यपालिका और विधायिका का बना हुआ ढांचा है उस ढांचे मे प्रतिबद्ध प्रशासनिक सेवा का प्रयोग अच्छा कदम माना जायेगा। संभव है कि इस प्रयास के विरूद्ध यह आरोप लगे कि इसमे प्रशासनिक सेवा मे संघ के लोग भरे जायेगे या आरक्षण प्रभावित होगा। यदि ऐसा कुछ होता भी है तब भी प्रशासनिक सेवा के लोगो की ब्लैकमेलिंग की तुलना मे यह संकट कम नुकसान का होगा। वैसे भी अधिकांश प्रशासनिक सेवा मे जे एन यू संस्कृति वालो का वर्चस्व रहा है। साथ ही आरक्षण के नाम पर भी निरंतर अव्यवस्था और वर्ग संघर्ष बढाने की कोशिश हुई है। यदि नये कदम से इन दो बीमारियो से आंशिक रूप से भी मुक्ति मिलती है तो इस कदम का पूरी तरह समर्थन किया जाना चाहिये।

सामयिकी

सारा भारत जानता है कि जे एन यू संस्कृति से जुडे सब लोग रोहित वेमुला की मौत को एक गंभीर घटना सिद्ध करते रहे। साम्यवादी अल्पसंख्यक गठजोड ने कई माह तक इस मामले को देश भर मे उछाला। राहुल गांधी ने भी अपनी सभाओ मे इस प्रकरण का लगातार उपयोग किया। मुददे को गरमाये रखने के लिये रोहित की मां को भी बार बार भीड के सामने प्रस्तुत किया गया।

अब पता चला है कि रोहित की मां को बीस लाख रूपये देने का वचन देकर उनका उपयोग किया गया। कई बार मांगने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। ज्यादा तगादा होने के बाद ढाई लाख रूपये मिलने की कहानी सुनी जा रही है। शेष साढे सत्रह लाख की सच्चाई भी सामने आनी चाहिये। वामपंथियो के विषय मे ऐसी तिकडम करना आम बात है किन्तु मुस्लिम संगठन भी अब वामपंथियो के साथ ऐसी बीमारी सीख लेंगे यह नयी बात सामने आ रही है। राहुल गांधी को भी यह राशि दिलवाने मे मदद करनी चाहिये।

सामयिकी

दिल्ली मे एक हिन्दू परिवार के सभी ग्यारह सदस्यो ने मोक्ष की कामना से आत्महत्या कर ली। यदि कभी शरीर मे कोई घाव होता है तो चारो तरफ से मक्खियां टूट पडती हैं। इस आत्महत्या की घटना से भी लाभ उठाने के प्रयास हुए। टी वी मे बैठकर सबने किसी न किसी तरह की हत्या का संदेह व्यक्त करना शुरू किया। कुछ लोगो ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। रिश्तेदारो ने भी हत्या कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगो ने किसी तांत्रिक का हाथ बताया तो किसी ने और कई संदेह व्यक्त किये जबकि मामला बिल्कुल सीधा दिखता है कि परिवार का कोई एक सदस्य मोक्ष की कामना से प्रभावित होकर धीरे धीरे पूरे परिवार की सोच उस दिशा मे मोडता रहा और पूरा परिवार उसके प्रभाव मे आकर उसकी सलाह से आत्महत्या के लिये तैयार हो गया।

किसी काल्पनिक सुख की कामना से खुशी खुशी आत्महत्या करने का यह पहला मामला नहीं है। आतंकवादी मुसलमान तो आम तौर पर ऐसा ही करते है। उन्हे स्वर्ग मे अनेक सुविधाओ का विश्वास करा दिया जाता है और वे उन कल्पनाओ को यथार्थ मानकर जान देने के लिये तैयार रहते है। फर्क यह है कि हिन्दुओ मे ये काल्पनिक सुविधाए सात्विक होती है तो

मुसलमानो मे तामसी । हिन्दुओ मे ऐसे प्रचार का दुरूपयोग कुछ स्वार्थी धर्मगुरू अपने लिये करते है तो मुसलमानो मे अपने संगठन विस्तार के लिये। यह ग्यारह आत्म हत्याओ का मामला कुछ भिन्न है क्योकि इसके पीछे कोई स्वार्थ नही है।

अनेक अन्ध श्रद्धा उन्मूलन संस्थाएं समाज मे लगातार प्रयास रत है और अन्ध श्रद्धा बढती जा रही है। सच्चाई यह है कि इन संस्थाओ का स्वयं का तरीका ठीक नही। ये संस्थाएं प्रायः व्यावसायिक है। खास बात यह है कि जब तक आप पर रोगी का विश्वास नही होगा तब तक आपका प्रभाव नही होगा। अन्ध श्रद्धा दूर करने का सरल उपाय है तर्क शक्ति जागरण। आज समाज मे एक वर्ग ऐसा है जो लगातार समझाता है कि तर्क से दूर रहना उचित है क्योकि तर्क किसी नतीजे तक नही पहुचने देता। दूसरी ओर बडी मात्रा मे लोग हर प्रकार की श्रद्धा का विरोध करते रहते है । ऐसे लोग ईश्वर तक का विरोध करने लगते है। दोनो ही अतिवाद घातक है। समन्वय की आवश्यकता है । हमलोगो ने एक छोटे से शहर मे प्रयोग किया। तर्क या अंध श्रद्धा का विरोध बिल्कुल नही किया और धीरे धीरे विचार मंथन का अभ्यास कराया तो परिणाम अच्छे आये । यदि कोई तर्क का विरोध करे तो उससे बचने की जरूरत है। कोई श्रद्धा को भी गलत बतावे तो दूरी बनाइयें। बीच का मार्ग ही ठीक है।

सामयिकी

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उप राज्य पाल के विवाद का निपटारा कर दिया। निपटारा किसके पक्ष मे हुआ यह मेरा विषय नही है। मै तो यह समीक्षा करना चाहता हूँ कि गलत कौन था। दिल्ली सरकार हाइकोर्ट उप राज्यपाल या केन्द्र सरकार । यह निर्णय उच्चतम न्यायालय का नही था बल्कि संविधान पीठ का निर्णय था।

सब जानते है कि भारत मे संविधान का शासन है। संविधान की जो व्याख्या केन्द्र सरकार ने की थी उसके अनुसार वह जो कर रही थी वह सही कदम था। उप राज्यपाल भी जो कर रहे थे उसमे कुछ भी गलत नही था क्योकि वे भी संविधान के अनुसार ही कार्य कर रहे थे। उच्च न्यायालय मे भी संविधान की सही व्याख्या की थी। उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नही कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले मे कोई हस्तक्षेप नही किया और मामला संविधान पीठ मे भेज दिया। संविधान पीठ ने इस मामले मे संविधान के शब्दो का भौतिक अर्थ और मूल भावना के बीच अंतर की व्याख्या की और निर्णय दिया की चुनी हुई सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है । उसे कोई अन्य इकाई सहायक के रूप मे उपयोग नही कर सकती। इसका अर्थ हुआ कि केजरीवाल भी अपनी जगह पर सही थे जो संविधान की मूल भावना को समझ रहे थे।

अब यह विवाद निपट जाना चाहिये परन्तु निपटेगा नही क्योकि केजरीवाल जी का संघर्ष दिल्ली सरकार चलाने तक सीमित नही है बल्कि प्रधान मंत्री की दौड मे स्वयं को आगे रखने का है। केजरीवाल नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध सबसे आगे रहने के लिये नये नये विवाद खोजते रहेंगे दूसरी ओर केन्द्र सरकार उनकी इच्छा के अनुसार उनपर कोई ऐसा प्रत्यक्ष आक्रमण नही करेगी जिससे उन्हे सहानुभूति मिले। केन्द्र सरकार चाहेगी कि किसी भी परिस्थिति मे केजरीवाल सरकार को बर्खास्त न किया जाय जो केजरीवाल लम्बे समय से प्रतिक्षा कर रहे है । दिल्ली की आम जनता से किसी को कोई मतलब नही है। क्योकि राजनेताओ की तो यह दुकानदारी है और संविधान उस दुकानदारी मे काम आने वाला तराजु और बांट। सारा दोष संविधान मे था जिसके कारण ये सारा विवाद पैदा हुआ और आज तक बना हुआ है।

प्रश्नोत्तर

1. मंगेश फटटोजी येनुरकर, राजगुरू वार्ड भंडारा महाराष्ट ज्ञान तत्व–888066

प्रश्न–1 साम्यवाद पूंजीवाद और समाजवाद इनकी अलग अलग परिभाषाए क्या हैं । आप कौन से वाद को पसंद करेंगे और क्यो?

2 डा0 बाबा साहेग अम्बेडकर ने निचली जाति, जनजातियों के उत्थान हेतु सिर्फ 10 साल का प्रावधान किया था आरक्षण के संबंध मे । यदि कांग्रेस पार्टी के राज्य मे आरक्षण खत्म हो जाता तो आज आरक्षण का मुददा नही मंडराता । आग के शोले की तरह मंडरा रहा है । इसका अंत कब होगा ।इसके लिये कौन जिम्मेदार ।

3 अभी अभी हिमाचल मे अतिक्रमण हटाने हेतु सुप्रिम कोर्ट के आर्डर के बावजुद होटल बिल्डिंग मालीक ने तैनात (कार्यवाही) लेडिज अधिकारी की गोली से छलनी करके मार डाला । हत्या कर दिया और फरार हो गया । इसका मलतब साफ है कि सुपर कोर्ट का कोई वैल्यु नही है। आप अपने विचार प्रकट करे।

4 हिन्दूवाद हिन्दू धर्म की परिभाषा क्या है? हिन्दू कार्ड आजकल पोलेटिकल पार्टिया इलेक्सन मे उपयोग रही है। इस विषय मे आपके विचार क्या है।

5 राहुल गांधी की टिप्पणी कोर्ट पर । कोर्ट का निर्णय अगर कांग्रेस पार्टी के हित मे फेवर मे आता है तो कोर्ट ठीक है। अगर उल्टा हुआ तो कोर्ट पर विश्वास नही क्यो?

उत्तर– 1 साम्यवाद और पूंजीवाद मे से मै साम्यवाद का पूरी तरह विरोधी हूॅ और पूंजीवाद को भी ठीक नही समझता । यद्यपि साम्यवाद की जो परिभाषा वर्तमान मे प्रचलित है वह साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की है। इसलिये उसे मै गलत मानता हूॅ । मै समाज सर्वोच्च मानता हूॅ और अर्थ व्यवस्था सहित सब प्रकार के निर्णय करने के अधिकार का अकेन्द्रीय करण चाहता हूॅ। इस अकेन्द्रीयकरण का नाम आप समाजीकरण दे सकते है। यदि समाजीकरण न हो तो निजीकरण हो सकता है जो पूंजीवाद का एक स्वरूप है।

2 बाबा साहब अम्बेडकर ने निचली जातियों के उत्थान के नाम पर अपनी राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिये आरक्षण का उपयोग किया । भीम राव अम्बेडकर एक बडे बुद्धिजीवी थे और पूरी तरह श्रम शोषण के पक्षधर थे । उन्होने बुद्धिजीवियों के लिये जीवन भर चिंता की किन्तु श्रमजीवियो के लिये कुछ नही किया । आज भी 90 प्रतिशत अवर्ण श्रमजीवी उसी तरह फटेहाल है। भले ही दो चार प्रतिशत अवर्ण बुद्धिजीवी सवर्ण बुद्धिजीवियो की तरह सुखी जीवन बिताने लगे हो । यह भीम राव अम्बेडकर की ही गलत नितियों का परिणाम है। फिर भी आज भारत जातिवाद साम्प्रदायिकता आर्थिक असमानता आदि से झुलस रहा है। यदि अम्बेडकर जी ने गांधी मार्ग का अनुकरण किया होता तो आज भारत इन समस्याओ के मुक्ति पा गया होता। मै इस पक्ष मे हूॅ कि श्रम मुल्य वृद्धि के लिये कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढाकर सब प्रकार के आरक्षण खतम कर दिये जाये साथ ही समान नागरिक संहिता लागु कर दी जाये।

3 न्यायपालिका को अपराध नियंत्रण मे सहायक तथा निरपराधो की रक्षक की भूमिका मे होना चाहिये। सुप्रिम कोर्ट अपराधियो के साथ अन्याय न हो इस बात की अधिक चिंता करता है। इसकी चिंता नही करता कि किसी निरपराध के साथ अपराधी ने अन्याय किया है। सुप्रिम कोर्ट को अपराध पीडित और अपराधी के बीच अपराधी को संदिग्ध मानना चाहिये किन्तु वह निरपराध मानता है। पुलिस और अपराधी के बीच न्यायालय को टतस्थ रहना चाहिये। किन्तु न्यायालय तटस्थ न होकर भी पुलिस को अविश्वसनीय मानता है।

4 हिन्दू धर्म की परिभाषा क्या है । इसकी मुझे साफ साफ जानकारी नही है। मै तो जैसा देखता हूॅ उस अनुसार समझता हूॅ कि हिन्दू एक जीवन पद्धति है कोई संगठन नही । जबकि अन्य धर्म मे जीवन पद्धति की जगह संगठन पर विश्वास करते है। जब संगठन शक्ति के आधार पर अन्य धर्म लगातार विस्तार कर रहे हो तब कुछ हिन्दुओ ने भी यदि वह गलत मार्ग पकडा है तो हम उसकी आलोचना कैसे कर सकते है।

5 राहुल गांधी ने अपने अल्प काल मे कुछ गंभीर गलतियां की है । उन्हे जे एन यू मे इतनी जल्दी जाकर खडा नही होना चाहिये। राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर भी अविश्वार व्यक्त नही करना चाहिये था। न्यायालय पर महाभियोग का प्रस्ताव देकर तो राहुल गांधी ने बहुत बडी गलती की।

2. वैद्य राज आहुजा भानु प्रतापपुर छ0ग0 ज्ञान तत्व– 460066

आपने लिखा है कि नरेन्द्र मोदी से आम जनता को जिस प्रकार उम्मीदे थी वे पूरी नही हुई है किन्तु पिछले 70 वर्षो मे जितने भी प्रधानमंत्री हुए है उन सबकी तुलना मे नरेन्द्र मोदी ने बहुत कम समय मे अच्छा काम किया है। मै पूछता हूॅ कि आम जनता की उम्मीदें भी पूरी नही हुई और अच्छा काम हुआ। जी एस टी, नोटबंदी को अच्छा काम नही माना जा रहा है। कौन सा विकास कार्य सब के साथ हुआ है? आरोप यह है कि हिन्दू मुस्लिम के अलावा कुछ नही हुआ। जनता प्रचार से वोट देती है काम से नहीं क्या ये सच है? कैसे भेद किया जा सकता है। पूर्व सरकार के और मोदी सरकार के कार्यकाल के हालात का?

उत्तर– जब किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की पिछले 70 वर्षो से तुलना होती है तब किसी वर्तमान शासक के गुण दोष की समीक्षा न करके पिछली सरकारो की तुलना होती है। गुण दोष की तुलना उस संभावित शासक से होती है जो भविष्य के लिये और अधिक अच्छा दिख रहा हो। नरेन्द्र मोदी से जिस तरह की उम्मीद थी उसका पूरा न होने का यह अर्थ नही है कि मोदी पिछली सरकारो की तुलना मे असफल है। यदि वर्तमान समय मे कोई ऐसा व्यक्ति या व्यवस्था दिख रही हो जो नरेन्द्र मोदी से भी अधिक अच्छा काम कर सकती है तब हम उससे समीक्षा कर सकते है। पिछली सरकारो से कोई तुलना व्यर्थ है क्योकि हर मामले मे उनकी तुलना मे कई गुना अच्छा काम हुआ है। जी एस टी एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसे पिछली सरकारे अच्छा समझते हुए भी कर नही पा रही थी क्योकि टैक्स चोरी करने वाले बहुत बडे समूह के विरोध का खतरा था। नोटबंदी के पूर्व भारत मे अवैध धन संग्रह की होड लगी हुई थी। नोटबंदी के बाद धीरे धीरे उसमे कमी आ रही है। आज हम नरेन्द्र मोदी से जिन समस्याओ के समाधान की उम्मीद कर रहे है वे समस्याए पिछले 70 वर्षो की शासन व्यवस्था की देन है। वर्तमान

सरकार के समय कोई भी समस्या बढी नही है भले ही घटने की गति उम्मीद से कम हो। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पूरी तरह रूक गया है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता परेशान है। ये दोनो समस्याए पिछली सरकार की देन है। 70 वर्षो मे जिन लोगो ने समस्याए पैदा की है वे तो कम से कम मोदी से प्रश्न नही कर सकते । मै समझता हूँ कि पिछली सरकार के समय लाभ उठा रहे लोग पूरी तरह नरेन्द्र मोदी के खिलाफ प्रचार अभियान मे एकजुट हो गये है।किन्तु यह भी संभावना है कि जिस तरह सन 77 के लगातार प्रचार के विरूद्ध गुप्त और अदृश्य लहर दिखी थी उसी तरह कोई चमत्कारिक परिणाम निकले और मोदी पूरी ताकत से उभरकर सामने आ जाये।

3 अनिल कुमार अनिल बिजनौर उत्तर प्रदेश ज्ञान तत्व – 150005

आरक्षण के नाम पर 2/4/18 को भारत बंद के दौरान हुआ नंगा नाच और गुंडई देश को किस दिशा मे ले जा रही है। 2014 मे एकजुट हिन्दू समाज 2019 मे बिखर जायेगा क्या? संघ के सेवा प्रकल्प कल्याण प्रोग्राम सामाजिक समरसता भी एकात्म का भाव न जगा सके। डा0 अम्बेडकर की आरक्षण की व्यवस्था देश को किधर ले जा रही है।

उत्तर– आपने समाज को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। कुछ लोग जाति के आधार पर बांटकर उसका लाभ उठाना चाहते है। कुछ लोग गरीब अमीर के बीच भी वर्ग विद्वेष बढाते है। मेरे विचार से वर्ग विद्वेष के ये सभी तरीके गलत है क्योकि व्यक्ति दो ही प्रकार के होते है । 1 जो सामाजिक नियमो का पालन करते हुए शरीफ या समझदार कहे जाते है तो दूसरे वे जो सामाजिक नियमो का उलंघन करके उससे लाभ उठाते है और चालाक या धूर्त कहे जाते है। ऐसे दोनो तरह के लोग हिन्दू भी हो सकते है और मुसलमान भी । सवर्ण भी और अवर्ण भी । इसलिये समाज को समाज ही रहने दीजिये । उसे हिन्दू मुसलमान मे बांटकर वर्ग विद्वेष मत बढाइये। संघ के कल्याणकारी प्रकल्प भी सफल नही हो रहे क्योकि संघ ने भी मोदी सरकार बनते ही अपनी समान नागरिक संहिता की मांग को पीछे करके हिन्दू राष्ट्र को आगे बढा दिया ।यदि आप धर्म के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करके उसका लाभ उठाना चाहते है तो यदि कोई दूसरा जाति के आधार पर लाभ उठाने का प्रयास करे तो उसकी आलोचना निंदा कैसे की जाये।

4 चितरंजन भारती पंचग्राम आसाम ज्ञान तत्व–029015

मंथन क्रमांक 80 ज्ञान यज्ञ क्यो क्या और कैसे? महत्वपूर्ण है। यह निष्कर्ष कि हर धूर्त यह प्रयत्न कर रहा है कि अन्य लोग समझदार न होकर शरीफ बने अर्थात भावना प्रधान हो, विचारोत्तेजक है । यह धूर्त कौन है इसे पहचानना ज्यादा मुस्किल नही है। आप विचार की प्रधानता पर जोर दे रहे है जो प्रशंसनीय है। हालांकि इतिहास देखे तो यही पायेंगे जो भी अच्छे बुरे कार्य (वह महान ही क्यो न हो) इसी भावना के बदौलत हुए हैं। आपका निष्कर्ष सही है कि भावना और विचार से समन्वय होना चाहिये। आपके अन्य निष्कर्ष भी सही है फिर भी वर्तमान की दशा दिशा देख निराशा होती है । आप फिर भी आशा का दीप जलाये है यह प्रेरक है महत्वपूर्ण भी। हम अपनी शुभकामना प्रेषित करते है।

उत्तर– आप ज्ञान तत्व पढते भी है और विचार मंथन भी करते है। ऐसे स्थिति मे निराशा का कोई काम नही है। पुराने समय मे भी इसी तरह अनेक मुददो पर निराशा मिलती थी जो बाद मे आशा के रूप मे बदल जाया करती थी। आज का वातावरण भी उससे अलग नही है। आशा निराशा एक साथ चलते रहते है। इसलिये आप जैसे गंभीर विद्वान को हमेशा आशा का दीप जलाये रखना चाहिये। अब ज्ञान यज्ञ परिवार इस कार्य मे और अधिक तीव्र गति से सक्रिय हो रहा है। हमलोग अपना कार्यालय दिल्ली से हटाकर हरिद्वार ले जा रहे है क्योकि दिल्ली राजनीति का अधिक और विचारो का कम केन्द्र है। इस संबंध मे वाराणसी हरिद्वार या ऋषिकेश अधिक उपयुक्त है जिसमे हमलोगो ने हरिद्वार को चुना है। ज्ञान यज्ञ परिवार के राष्टीय संयोजक के लिये रीवा निवासी प्रसिद्ध अधिवक्ता अभ्युदय द्विवेदी को चुना गया है। आचार्य पंकज जी परिवार के संरक्षक के रूप मे है। ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान यज्ञ के माध्यम से शराफत और चालाकी या भावना और बुद्धि के समन्वय के परिणाम स्वरूप देश भर मे समझदारी विकसित होने को अपनी सफलता मानता है। पूरा प्रयास इस दिशा मे किया जायेगा आपसे भी सहयोग समर्थन मार्ग दर्शन मिलता रहेगा।